पूंजीगत सामानों की आयात सीमा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक का दबाव

4606. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने पूंजीगत सामानों की आयात-सीमा बढ़ाने के लिए सरकार पर दबाव डाला था और भारत सरकार अब तक इस दबाव के आगे नहीं झुकी है लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ सीमा तक पूंजीगत सामानों के आयात को आसान बना दिया है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं के लिए आयात सीमा उदार बनाई गई तथा यह आदेश किस तारीख से प्रभावी हुआ है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और आयात पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) से (ग) जी, नहीं। पूंजीगत वस्तुओं के लिए आयात सीमा बढ़ाने के संबंध में विश्व बैंक की तरफ से कोई दबाव नहीं रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा संकट के दौरान लगाए गए प्रतिबन्धों को प्रसामान्यीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप से हटा लिया गया है। इस प्रकार, पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा शीघ्र जारी करने की प्रक्रिया को सुकर बनाने की दृष्टि से अब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत डीलरों को, कोई अधिकतम सीमा रखे बिना, विदेशी मुद्रा जारी करने की अनुमति दे दी गई है। इसके अलावा, विदेशी मुद्रा ऋणों के उपयोग और पूंजीगत वस्तुओं के आयात का वित्तपोषण करने के प्रयोजन के लिए वित्तीय संस्थाओं के साथ उधार श्रृंखलाओं के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध हटा लिए गए हैं।

भारतीय रुपए का मूल्य

4607. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या वित्त मंत्री 25 फरवरी, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 144 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रुपए के बार-बार अवमूल्यन के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा विदेशी ऋणों के प्रतिसंदाय के लिए कितनी अधिशेष धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ख) इस अवमूल्यन का मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान किस-किस तिथि को भारतीय रुपए का अधिमूल्यन किया गया था तथा उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): (क) रुपए के अवमूल्यन के कारण रुपए में ऋण की वापसी अदायगी की अतिरिक्त राशि उस प्रत्येक संबंधित विदेशी मुद्रा के प्रति रुपए के अवमूल्यन पर निर्भर करती है जिसमें ऋण निर्धारित किया गया है। चूंकि ऋण की वापसी अदायगियां अनेक मुद्राओं में की जाती है और विनिमय दर में बार-बार परिवर्तन होते हैं, अवमूल्यन के कारण रुपए में ऋण की वापसी अदायगी में वृद्धि की वास्तविक राशि की मात्रा बताना कठिन है।

(ख) चूंकि विदेशी व्यापार भारत के सकल घरेलू उत्पाद के बहुत कम समानुपात में होता है, इसलिए अवमूल्यन का मुद्रास्फीति पर प्रभाव थोड़ा है।

(ग) पौंड स्टर्लिंग जो कि एक हस्तक्षेप मुद्रा थी की तुलना में अप्रैल, 1990 फरवरी, 1992 के दौरान की तारीखें और रुपए में उद्यर्वमुखी संशोधन की राशि (प्रतिशत में) अनुपत्र में दर्शायी गई है।

[देखिये परिशिष्ट 162, अनुपत्र संख्या 98]

विभिन्न योजनाओं के अधीन जमा कराई गई विदेशी मुद्रा का उपयोग

4608. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या वित्त मंत्री 25 फरवरी, 1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 130 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रेषण योजनाओं के अधीन जमा की गई विदेशी मुद्रा को सरकार किन-किन उद्देश्यों के लिए प्रयोग में ला रही है तथा इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर): विदेशी मुद्रा प्रेषण योजनाओं की शुरुआत भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने हेतु विदेशी मुद्रा जुटाने के लिए की गई थी और इस उद्देश्य की प्राप्ति इस प्रकार की प्रेषणाओं के कारण विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि किए जाने से संभव हो गई है।